भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट–बड़ासी, देहरादून।

संख्या 1110 / मु0ख0 / खनन / 66 / सोपस्टोन / भू0खनि0ई0 / भू0खनि0ई0 / 2019–20, दिनांक 18 जून 2022

कार्यालय–ज्ञाप

मै0 देवी भगवती मिनरल्स, वैशाली कालोनी, हल्द्वानी जनपद नैनीताल (भागीदार–1 श्रीमती रूची साह पत्नी श्री मनोज साह, ग्राम व पोस्ट झूतिया, पट्टी रामगढ, तहसील व जिला नैनीताल। 2– श्री अनिल गडिया पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी एसलेड कम्पाउण्ड, सूखा ताल, नैनीताल 3– श्रीमती ममता साह पत्नी श्री मुरारी लाल, निवासी ग्राम बोहराकोट, पट्टी रामगढ तहसील व जिला नैनीताल) के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 963 / VII-A-I / 2021 / 1(9) / 21 दिनांक 07 जनवरी 2022 के द्वारा जनपद बागेश्वर की तहसील काण्डा के ग्राम ढपटी के क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत एवं सीमांकित कुल 20.513है0 मध्ये 19.120 है0 भूमि में खनिज सोपस्टोन का 50 वर्ष की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत एवं सीमांकित क्षेत्रफल की खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762 / खनन / गौण खनिज–माईनिंग प्लान / 26 / भू0खनि0ई0 / 2015–16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844 / VII-1 / 2015 / 68–ख / 2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589 / VII-1 / 2015 / 68–ख / 2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति– 2015 के प्रस्तर–3(दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, श्री पंकज पाण्डे, आर0क्यू0पी0 पंजीकरण संख्या मु0ख0 / RQP/DDN/04/2016 के द्वारा तैयार की गयी खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संकियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के प्रथम वर्ष में 30035टन, द्वितीय वर्ष में 31284 टन, तृतीय वर्ष में 33737टन, चतुर्थ वर्ष में 34694 टन एवं पंचम वर्ष में 35132 टन के उत्पादन हेतु प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :–

शर्ते / प्रतिबन्धः–

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन खनन पट्टे के पंजीकरण के दिनांक से अगामी 05 वर्ष की अवधि हेतु किया जा रहा है।
2. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
3. खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना / विषय वस्तु का संगुप्त रखना / छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
4. खनन कार्य एवंम खनिजों के खनिज अन्वेषण / खनिज भण्डारण / खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
5. आवेदक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्व मशीनीकृत माइनिंग हेतु रू0 2.00 लाख बैंक गारन्टी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म मशीनीकृत हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. आवेदक द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 963 / VII-A-I / 2021 / 1(9) / 21 दिनांक 07 जनवरी 2022 द्वारा निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की शर्त संख्या–6के अनुसार आवेदक द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601(अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश सं0 1621 / VII-1 / 212–ख / 2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना होगा एवं तद्नुसार पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
7. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।

8. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।
9. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
10. इस खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
11. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
12. व्यसायिक सुरक्षास्वास्थ्य और काम करने की स्थिति Code-2020 की अनुपालना की जानी होगी।
13. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
14. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
15. भू–सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू–संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होगें।
16. अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

संलग्नकः खनन योजना
एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना
की अनुमोदित प्रति।

18/6/22
(एस0 एल0 पैट्रिक)
निदेशक।

संख्या 1110 / मु0ख0/खनन/66/सोपस्टोन/भू0खनि0ई0/भू0खनि0ई0/2019–20, तददिनांकित

प्रतिलिपिः **निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :**

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
5. मै0 देवी भगवती मिनरल्स, वैशाली कालोनी, हल्द्वानी जनपद नैनीताल ।
6. श्री पंकज पाण्डे, आर0क्यू0पी0 ।

18/6/22
(एस0 एल0 पैट्रिक)
निदेशक।